



कनाडा की त्रूदो सरकार द्वारा आतंकवाद से संबंधित रिपोर्ट से खालिस्तानी चरमपंथ के संदर्भों को हटाने के पीछे उनकी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भले हों, लेकिन इसका दोनों देशों के संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भड़काने वाला कदम

कनाडा

की जस्टिन त्रूदो सरकार द्वारा आतंकवाद से संबंधित अपनी एक अहम रिपोर्ट से खालिस्तानी चरमपंथ से संबंधित संदर्भों को हटाने की भारत में स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रिया हुई है। 2018 में जारी की गई मूल रिपोर्ट में कनाडा के लिए पांच तरह के आतंकी खतरों का जिक्र किया गया था, जिनमें सुन्नी इस्लामिस्ट एक्स्ट्रीमिज्म, राइट विंग एक्स्ट्रीमिज्म, शिया एक्स्ट्रीमिज्म और कनाडियन एक्स्ट्रीमिज्म ट्रेवलर्स के साथ ही स्वतंत्र खालिस्तान की मांग करने वाले सिख एक्स्ट्रीमिज्म शामिल था। मगर कनाडा की सरकार ने 12 अप्रैल को इस रिपोर्ट से खालिस्तान से संबंधित संदर्भों को हटा दिया। वास्तविकता यह है कि खालिस्तान अलगाववाद और आतंकवाद

का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसे कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में बसे आतंकवादियों के समर्थन के साथ ही खालिस्तान के रास्ते से भी खालिस्तानी मिलता रहता है। वहीं 2015 में कनाडा का प्रधानमंत्री बनने के बाद से जस्टिन त्रूदो और उनकी लिबरल पार्टी ने खालिस्तानी आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाया है, क्योंकि यह माना जाता है कि उनकी जीत में खालिस्तानी चरमपंथी गुटों के समर्थन की बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से भारत से उनके रिश्ते सहज नहीं रहे हैं, जिसका असर फरवरी, 2018 में उनके भारत प्रवास के समय भी देखा गया था। उस प्रवास के दौरान उनके एकाधिक कार्यक्रमों में खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल की कथित मौजूदगी भारत को नागवार गुजरी थी। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने

त्रूदो से मुलाकात के दौरान उन्हें कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक गुटों और राजनीतिक दलों की एक सूची भी सौंपी थी। इस पर कार्रवाई करना तो दूर, खुद त्रूदो ने खालिस्तान समर्थक कार्यक्रमों में शिरकत करने से गुरज नहीं किया। कनाडा सरकार के ताजा कदम पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भारत सहित वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंताजनक बताया है, तो इसके कारणों को समझने की भी जरूरत है। दरअसल कनाडा में इसी वर्ष अक्टूबर में चुनाव होने हैं और इस कदम को वहां बसी सिख आबादी को लुभाने की त्रूदो की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। त्रूदो ने सिख समुदाय का समर्थन जुटाने में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसका भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है।

नोटा आइटम सांग नहीं



नोटा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि मतदाता राजनीतिक दलों को प्रारिचित करने के लिए मजबूर कर सकें। नोटा के पीछे की भावना के स्वरूप और वितरण में सुधार के लिए ठोस संवाद और योजना की जरूरत है।

शंकर अय्यर, आईडीएफसी इंस्टी. में विजिटिंग फेलो



मतदाताओं की नाराजगी की काफी अनदेखी की गई है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां विभिन्न कारकों को चुनती हैं—जाति से लेकर पंथ तक, लोकप्रियता से लेकर वंशावली तक और धन से लेकर बाहुबल तक। पूर्व में किए गए अपराध उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। चाहे यह मुंबई हो, नीलगिरी, दाहोद, सिंधभूम या और कहीं, लगता है, नोटा अभी तक राजनीतिक दलों के चुनाव विश्लेषण में कोई कारक नहीं बन सका है।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) का विश्लेषण बताता है कि पहले चरण के चुनाव में 91 लोकसभा सीटों के लिए 1,266 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 213 आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उनमें से 146 के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हैं, 12 के खिलाफ दोष सिद्ध हो चुका है, दस पर हत्या के आरोप हैं, 25 पर हत्या की कोशिश के आरोप हैं, तो 16 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले

हैं। प्रमुख दलों में से भाजपा के 83 में से 16, कांग्रेस के 83 में से 22, वाईएसआर कांग्रेस के 25 में से 10 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले का खुलासा किया है। लोकसभा चुनावों के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे 96 उम्मीदवारों में से 24 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 17 पर गंभीर अपराधों के मामले हैं। मेरठ के 11 प्रत्याशियों में से पांच के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।

राजनीतिक प्रक्रियाओं में पवित्रता कभी पर्याप्त नहीं होती है—ऐसा पूरा जो परिणाम के इरादे को आगे बढ़ाता है, वह अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। यह सच है कि राजनीतिक दलों ने नोटा के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है, लेकिन यह भी तथ्य है कि नोटा के वोटों ने अभी तक यथास्थिति को बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण जन समर्थन हासिल नहीं किया है। इसका कुछ कारण नोटा के डिजाइन में निहित है। वैचारिक रूप से नोटा के वर्तमान स्वरूप में उस अनिवार्य वजन का अभाव है, जो मतदाताओं को यह सोचने के लिए विवश करे कि यह प्रत्याशियों और राजनीति के घटिया स्तर के खिलाफ एक प्रभावी औजार है। नोटा नाराजगी दर्शाने का सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन जहां तक परिणामों की बात है, तो चाहे मानें या न मानें, नोटा का बटन प्रभावी असर नहीं डाल सका है।

इसलिए नोटा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि मतदाता राजनीतिक दलों को प्रारिचित करने के लिए मजबूर कर सकें। नोटा के पीछे की भावना के स्वरूप और वितरण में सुधार के लिए ठोस संवाद और योजना की जरूरत है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय के चुनाव में पुनर्निर्वाचन पर विचार करने की बात कही है, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को नोटा से कम वोट मिलता है। यदि चुनाव में जीत का अंतर नोटा के वोटों से कम हो, तो फिर

से चुनाव कराना एक प्रभावी उपाय होगा।

नोटा के पुनर्गठन को प्रकट और चुनावी नतीजों से परे देखने की जरूरत है। नोटा का उद्देश्य राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों और राजनीति में सुधार के लिए मजबूर न सही, राजी करना जरूर है। मसलन, चुनावों में आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों को राजनीति में आने से रोकना जरूरी है। कम से कम संज्ञेय आपराधिक मामलों का सामना करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन भरने से हतोत्साहित करने का एक उपाय यह है कि उम्मीदवार को मिले वोट का कुछ फीसदी नोटा में डाल दिया जाए।

मौजूदा चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी की गुणवत्ता को लेकर भारी दुख और शोक है—स्पष्टतः दुर्व्यवहार से लेकर कट्टरता तक। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बस इतना हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ नेताओं पर थोड़े समय के लिए प्रचार कार्य पर पाबंदी लगा दी है। जब भी उम्मीदवार शालीनता की सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो उस पर रोक के लिए हर बार उनको मिले वोटों को नोटा के खाते में क्यों नहीं डाला जाता। यदि क्रिकेट में दुर्व्यवहार के लिए एम एम धोनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, तो राजनेताओं पर क्यों नहीं? इसके अलावा और भी उपाय हैं और होंगे। लेकिन इन उपायों को लागू करने के लिए कानून, नियमों का मसौदा तैयार करने और उनका निरीक्षण करने की जरूरत होगी। यह सब कठिन लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। चंद्रशेखर द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त टी. एन शेषन के समय निर्वाचन आयोग कोई दूसरा ही संस्थान था, जिसे बुजुर्गों से मिटा दिया गया। शेषन ने राजनीतिक विकृति पर नकेल कसने के लिए कानून को उसकी भावना के साथ लागू किया था। सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में नोटा का विचार आइटम गीत नहीं हो सकता है।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 60.02 लाख मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। यानी भाजपा को कुल जितने वोट मिले थे, उसका 3.49 फीसदी या कांग्रेस को कुल जितने वोट मिले थे, उसका 5.61 फीसदी। इनमें से 5.92 लाख से ज्यादा मतदाता उत्तर प्रदेश से थे। राष्ट्रीय चार्ट में जहां नीलगिरी 16,559 वोटों के साथ शीर्ष पर है, तो रॉबर्ट्सगंज 18,489 वोटों के साथ उत्तर प्रदेश के चार्ट में शीर्ष पर है। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया, जो बहुमत पाने वाली पार्टी भाजपा को मिले कुल वोट का 2.2 फीसदी है, बसपा के वोटों का 3.9 फीसदी, सपा के वोटों का चार फीसदी, कांग्रेस के वोटों का 13 फीसदी और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले वोटों का 33 फीसदी है। अगर नोटा कोई पार्टी होता, तो यह सातवें स्थान पर होता।

नोटा यानी उपर्युक्त उम्मीदवारों में से कोई नहीं की सुविधा भारतीय मतदाताओं को सितंबर, 2013 से उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विकल्प के प्रति अपनी नाराजगी या असंतोष को व्यक्त कर सकें। नोटा का बढ़ता ज्वार राजनीति और उम्मीदवारों की गुणवत्ता के प्रति मतदाताओं के असंतोष और असहमति को दर्शाता है। 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इसने अनुमानित रूप से 22 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के अंतर को प्रभावित किया।

अब जबकि भात अगली लोकसभा के लिए मतदान कर रहा है, तो यह पूछना लाजिमी है कि क्या मतदाताओं को इस असहमति को राजनीतिक दलों की स्वीकृति या सुशासनिक प्रतिक्रिया मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की समीक्षा करें, तो वह दर्शाता है कि

मंजिलें और भी हैं

>> वीनू डेनियल

पर्यावरण अनुकूल मकान बदल सकते हैं जीवन

मैं मूलतः केरल का ही रहने वाला हूँ। हालांकि मेरे माता-पिता को पश्चिम एशिया जाना पड़ा था और मेरा जन्म भी वहीं हुआ। मैं संगीतकार बनना चाहता था। मगर मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं किसी पारंपरिक पेशे से जुड़ जाऊँ। अबू धाबी में स्कूली पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2000 में मैं केरल लौट आया और मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिवेंद्रम (सीईटी) में आर्किटेक्ट में दाखिला ले लिया। आर्किटेक्टर की पढ़ाई करने के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि इसमें रचनात्मकता की काफी गुंजाइश है, जिसके जरिये मैं खुद को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। इसके बावजूद मुझे सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या कुछ होने वाला है।

कॉलेज में एक दो वर्ष के भीतर ही मुझे पारंपरिक आर्किटेक्ट की पढ़ाई के शैक्षणिक ढांचे को लेकर काफी गुस्सा आया। इसके साथ तालमेल बिठा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मगर कॉलेज के चौथे वर्ष में मुझे महान आर्किटेक्ट लॉरी बेकर से मिलने का मौका मिला और फिर मेरी दिशा ही बदल गई। बेकर ने बताया कि किस तरह से इमारतें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में रह सकती हैं और अनावश्यक गंदगी और कचरों से बचा जा सकता है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कैसे उन्हें एक बार महात्मा गांधी से मिलने का अवसर मिला और वह क्षण उनके लिए कितना महान बन गया। बेकर के मुताबिक, गांधी के विचार ने उन्हें खासा प्रभावित किया, जिससे वह समझ पाए कि किसी आदर्श गांव में कोई आदर्श मकान वह होगा, जिसे ऐसी सामग्री से बनाया जाए, जो वहां पांच मील के दायरे में उपलब्ध हो। वाकई बेकर ने यह जो लिखा है, वह बहुत प्रेरणादायक है। आज हम जब अपने चारों ओर देखते हैं, तो लगता है कि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण में अवशेष और मलबों के भी इस्तेमाल की जरूरत है। इससे लाखों लोगों की आवासीय समस्या खत्म हो

सकेगी और इससे पर्यावरण पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा। मैं जब कॉलेज में ही था, उस समय 2004 में आई भीषण सुनामी ने काफी तबाही मचाई थी। 2005 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से संबद्ध ओरविले अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ सुनामी के बाद हो रहे पुनर्निर्माण कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। इसके बाद 2007 में मैंने अवशेषों से निर्माण करने के लिए वॉलमेकर्स नाम से अपनी कंपनी बना ली। उस समय मैं 26 वर्ष का था। मुझे पहला काम एक परिसर के अहाते की दीवार बनाने का मिला, जिसे हमने मलबों में पड़ी मिट्टी की इंटों और बीयर की बेकार बोतलों से बनाया। 2008 में कैसर के एक मरीज के लिए हमने कम लागत वाला और पर्यावरण के अनुकूल घर बनाया, जिसकी वजह से मुझे वेब पेरियार पाल्पुशन कंट्रोल कमेटी ने पुरस्कृत भी किया। शुरु में मुझे लोगों को समझाने में काफी अड़चन आई। लोग संवहनीय निर्माण को समझना ही नहीं चाहते थे। उन्हें डिजाइन को लेकर मेरे विचार पसंद नहीं आ रहे थे। आखिरकार मेरे मामा ने मुझे अपना मकान बनवाने की जिम्मेदारी दी। मैंने उनके लिए जो कॉटेज बनाया, उसमें मिट्टी की इंट इस्तेमाल की। मकान की डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इस कॉटेज को पुरस्कृत भी किया गया। मेरे नाम से आज दो पेटेंट हैं, एक है डेबेरीज वॉल और दूसरा है शर्टर्ड डेबेरीज वॉल।

पर्यावरण पर भारी पड़ते चुनाव

चुनाव आयोग ने सभी दलों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में प्रचार सामग्री के रूप में एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी थी, पर क्या महज सलाह देने से ही राजनीतिक दल कार्रवाई करेंगे?



मुकुल श्रीवास्तव

जलाना पड़ता है या लैंडफिल में डाला जाता है। एक प्रतिशत से भी कम पीवीसी को रिसाइकिल किया जाता है। जलता हुआ पीवीसी बहुत-सी जहरीली गैस छोड़ता है, जो हवा से भारी होती है और जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे कैसर होने की आशंका होती है। उसकी राख जमीन और पानी को भी प्रदूषित कर देती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो से तीन महीनों में अनुमान के अनुसार प्लास्टिक की खपत इतनी होती है, जितनी दो या तीन गैर-चुनावी वर्षों में होती है। ये एक कैसरकारी तत्व है, जिसके कारण देश भर में ग्राम सरकारें इसके उपयोग में कटौती करने के लिए प्रयत्न हो रही हैं।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार, केंद्र

सरकार ने भी एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा है, जिसका 1.34 करोड़ टन प्रति वर्ष देश में निर्मित किया जाता है। प्रचार विज्ञापनों के लिए कपड़े और पुनर्नवीनीकरण कागज जैसे विकल्प ज्यादा पर्यावरण मैत्री हो सकते हैं। पीवीसी के लिए पचास साल की तुलना में सूती कपड़े को सड़ने में केवल पांच से छह महीने का समय लगता है। इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री के रूप में एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी थी, लेकिन क्या महज सलाह देने से ही राजनीतिक दल कार्रवाई करेंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। अगर यह प्रतिबंध आदर्श आचार संहिता का हिस्सा बन जाता है, तो इसे (प्लास्टिक) सीमित करने का एक निश्चित तरीका जरूर बन सकता है। इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को दक्षिणी राज्य में पीवीसी-आधारित प्रचार सामग्री से बचने का निर्देश दिया है। तस्वीर का दूसरा हिस्सा यह भी है कि देश में लोग न तो पर्यावरण को कांति समझते हैं और न ही इंसानी जान की। ये चुनाव, चुनाव प्रचार में व्यवहार परिवर्तन और नई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शानदार अवसर हो सकते हैं, पर फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

हरियाली और रास्ता

मीनार की ऊंचाई और नन्हा मेंढक

एक मेंढक की कहानी, जो बहरा होने के कारण दूसरों की बातों से विचलित नहीं हुआ और सफल हो सका।

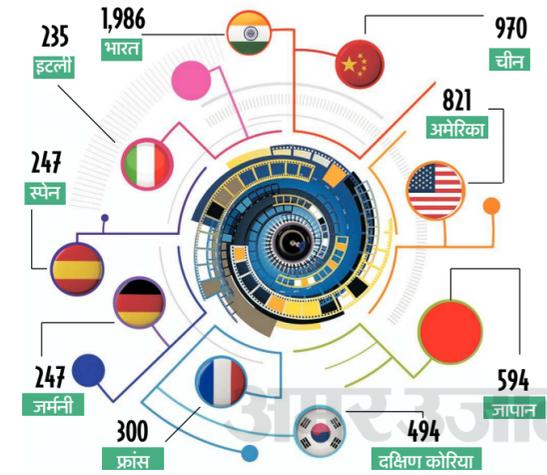


एक बार कुछ नन्हे मेंढकों में एक अनोखी शर्त लगी। शर्त थी-एक लंबी-सी मीनार की चोटी तक पहुंचने की। मौसम बारिश का था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छोटे मेंढकों की इस टोली में से कोई भी मीनार की चोटी तक पहुंच पाएगा। सभी मेंढक टर-टर करके नन्हे मेंढकों की हौसला अफजाई करने आ गए। नियत समय पर मुकाबला शुरू हुआ। तभी एक बुजुर्ग मेंढक ने कहा, 'अरे बहुत मुश्किल है रे। मीनार बहुत ऊंची है।' एक दूसरे मेंढक ने कहा, 'बच्चे ही तो हैं। इतनी ऊंची मीनार पर तो बड़ों को भी पहुंचने में नानी याद आ जाएगी।' लेकिन नन्हे मेंढकों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उनके लिए तो यह अपने हुनर को दिखाने का एक सुनहरा मौका था। तभी देखने में आया कि एक छोटा मेंढक फिसलकर नीचे गिर गया। और फिर एक दूसरा मेंढक भी गिर गया। और फिर तीसरा। जैसे-जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे नन्हे मेंढकों के फिसलने का भी सिलसिला बढ़ता जा रहा था। लेकिन उनमें से एक मेंढक बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा था। धीरे-धीरे बाकी सभी मेंढक फिसलकर नीचे पहुंच गए। लेकिन उनमें से एक मेंढक बड़ी मुश्किली के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते वह नन्हा मेंढक चोटी पर पहुंच ही गया। आखिर क्या बात थी कि वह मेंढक सफल हो गया, जबकि बाकी सभी मेंढक फिसल गए? दरअसल वह मेंढक बहरा था। उसको कभी किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसकी नजर केवल अपने लक्ष्य पर थी। पीछे दर्शक मेंढक क्या बोल रहे थे और कैसी-कैसी अटकलें लगा रहे थे, इससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। अक्सर दूसरों की सुनने के कारण हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और अपने प्यारे ख्वाबों से हाथ धो बैठते हैं।

हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अन्य चीजों पर नहीं।

खुली खिड़की सर्वाधिक फिल्म निर्माण भारत में

दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में हमारे देश में ही बनाई जाती हैं, उसके बाद चीन और अमेरिका का स्थान है। वर्ष 2017 में हमारे देश में सर्वाधिक 1,986 फिल्में बनाई गईं।



संन्यासी की क्षमा याचना

स्वामी विवेकानंद नए-नए संन्यासी बने थे। वह तब तक प्राणिमात्र में ईश्वर के दर्शन का संदेश समझ नहीं पाए थे। युवावस्था में वह काफी समय तक ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करने में लगे रहे। वह गांवों की स्थिति का अध्ययन करते और लोगों को सदाचारी बनने और दुर्व्यसनों से दूर रहने का उपदेश दिया करते थे। एक दिन भीषण गर्मी में स्वामी जी एक गांव से गुजर रहे थे। प्यास लगी, तो खेत की मेड़ पर बैठे एक व्यक्ति को लोटे से पानी पीते देखकर कहा, भैया, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। उस ग्रामीण ने भनावा वस्त्रधारी संन्यासी को देखकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं निम्न जाति का व्यक्ति आपको अपने हाथों से पानी पिलाकर पाप मोल नहीं ले सकता। स्वामी जी यह सुनकर आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों में उन्हें लगा कि मैंने साधु बनने के लिए जाति, परिवार तथा पुरानी प्रचलित गलत मान्यताओं का परित्याग कर दिया, फिर आग्रह करते उस निश्चल ग्रामीण का पानी क्यों नहीं स्वीकार किया? मेरा सोया जाति अभिमान क्यों जाग उठा? यह तो अधर्म ही गया। वह तुरंत उस किसान के पास लौटकर बोले, भैया, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम जैसे निश्चल परिश्रमी व्यक्ति के हाथों पानी न पीकर घोर पाप किया है। निम्न जाति तो उसकी होती है, जो दुर्व्यसनी और अपराधी होता है। स्वामी जी ने उसके हाथ से लोटा लेकर पानी ग्रहण किया। बाद में वह खुलकर ऊंच-नीच की भावना पर प्रहार करते रहे।